



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939
No. 4]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

का.नि.आ. 5(अ).—निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी संपत्ति नियम, 1925 को अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की धारा 346 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की नोटिस, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पूर्व विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, निदेशक (भूमि और छावनी) रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली- 110011 को भेजा जा सकेगा।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी संपत्ति नियम, 2017 है।

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण भारत की छावनियों पर है।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.**—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात संदर्भ से अपेक्षित न हों;

(क) “अधिनियम” से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) “स्थायर संपत्ति” में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे और भूवद्ध वस्तुएँ, जो स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी चीजें हैं, सम्मिलित हैं किन्तु इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसल, या घास सम्मिलित नहीं हैं;

(ग) “जंगम संपत्ति” में भूमि पर खड़ा काष्ठ, उगती फसल व घास, पेड़-पौधों पर लगे फल तथा उनका रस, छाल, लाख और स्थावर संपत्ति के सिवाए अन्य विवरण वाली सभी संपत्ति सम्मिलित हैं;

3. **छावनी संपत्ति का रजिस्टर-** उन स्थावर सम्पत्तियों का, जो छावनी बोर्ड में निहित हैं या उसकी हैं, रजिस्टर वर्तमान लेखा कोड के संगत नियमों में विहित प्ररूप में छावनी बोर्ड द्वारा बनाए रखा जाएगा और छावनी बोर्ड की सभी धृतियों में परिवर्धन या परिवर्तन को उसमें अभिलिखित किया जाएगा।
4. **केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि से भिन्न भूमि का क्रय या पट्टा.**—अधिनियम की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार में निहित संपत्ति से भिन्न किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का क्रय कर सकेगा या पट्टे पर ले सकेगा जो छावनी के प्रशासन से संबन्धित किसी और निश्चित प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो :

परंतु छावनी बोर्ड, कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की मंजूरी, जोकि ऐसी मंजूरी को स्वीकृत या अस्वीकृत करने से पहले प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा की टिप्पणी अभिप्राप्त करेगा, के सिवाय, छावनी की सीमाओं के भीतर किसी ऐसी संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

5. **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन भूमि अर्जन का आवेदन -** छावनी बोर्ड, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 124 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करते समय अर्जन किए जाने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताएगा तथा संदाय किए जाने वाले और प्रेषित किए जाने वाले प्रतिकर का प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा तथा छावनी बोर्ड यह भी प्रमाणित करेगा कि प्राइवेट संविदा द्वारा अर्जन असाध्य या विशेष कारणों से अवांछनीय पाया गया है।
6. **केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि का छावनी बोर्ड को अंतरण.**—जब छावनी में किसी ऐसी भूमि की, जो केन्द्रीय सरकार में निहित है, छावनी प्रशासन से संबंधित प्रयोजन के लिए छावनी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तब छावनी बोर्ड, उन कारणों को बताते हुए कि वह क्यों अपेक्षित है और वह प्रयोजन दर्शाते हुए जिसके लिए वह अपेक्षित है, भूमि की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि केन्द्रीय सरकार विचार करती है कि आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए तब ऐसी शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे, भूमि को छावनी बोर्ड को अंतरित कर सकेगी:

- (क) यदि ऐसी भूमि जिसके लिए आवेदन किया गया है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए पहले से ही अधिभोग में है, तब ऐसी भूमि का छावनी बोर्ड को अंतरण, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के नियम 7 या प्रवृत्त छावनी भूमि प्रशासन नियमों के सुसंगत नियमों के उपबंधों के द्वारा शासित होगा; या
- (ख) यदि भूमि ऐसे उद्देश्य के लिए अपेक्षित है, जिससे छावनी बोर्ड को किसी प्रकार की आय व्युत्पन्न होगी, तब ऐसी भूमि ऐसी रीति में की गई अदायगी पर जो केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक मामले में समुचित समझे, अंतरित की जा सकेगी;
- (ग) यदि किसी भी समय भूमि का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए वह छावनी बोर्ड को मंजूर की गई है, या केन्द्रीय सरकार की राय में किन्हीं अन्य शर्तों के भंग होने पर, जिन पर भूमि छावनी बोर्ड को अंतरित की गई थी, या ऐसी भूमि साधारण लोकहित में अपेक्षित है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसी भूमि पर फिर कब्जा कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार से कब्जा की गई किसी भूमि के संबंध में छावनी बोर्ड को संदेय प्रतिकर की रकम का विनिश्चय प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और ऐसी रकम, किन्हीं भी परिस्थितियों में उस भूमि के अंतरण के लिए छावनी बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदत्त, रकम, यदि कोई हो, के साथ उस पर निर्मित भवन, यदि कोई हो, की प्रारम्भिक लागत या वर्तमान मूल्य से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

7. **छावनी बोर्ड द्वारा स्थावर संपत्ति का अंतरण.**—ऐसी स्थावर संपत्ति को, जो छावनी बोर्ड में निहित है और उसकी है, छावनी बोर्ड, किसी व्यक्ति को बिना प्रीमियम के पट्टे से भिन्न विक्रय, बंधक या विनिमय द्वारा या अन्यथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे, अंतरित नहीं करेगा:

परन्तु यदि स्थावर संपत्ति छावनी की सीमाओं से परे अवस्थित है, तो राज्य सरकार के विचार जो कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित किए जाएंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी मंजूरी देने से पूर्व, विचार में लिए जाएंगे।

8. छावनी बोर्ड द्वारा पट्टा.—अधिनियम की धारा 267 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह स्थावर संपत्ति जो छावनी बोर्ड में निहित है और उसकी है, छावनी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रीमियम के बिना पट्टे पर दी जा सकेगी :-

- (i) पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के दौरान एक युक्ति-युक्त भाटक आरक्षित हो और संदेय हो या विकल्प के रूप में प्रधान निदेशक द्वारा सम्यक अनुमोदित उपयुक्त राजस्व उत्पादन आदर्श प्रकल्पित हो;
- (ii) पट्टा या पट्टे के लिए किया गया करार, छावनी बोर्ड के साधारण अधिवेशन में किए गए संकल्प द्वारा उसकी पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अवधि के लिए या कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी अवधि के लिए जो बीस वर्ष से अधिक है और तीस वर्ष से अधिक नहीं है या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी अवधि के लिए जो तीस वर्ष से अधिक है, नहीं किया जा सकता;
- (iii) ऐसे प्रयोजन के लिए पट्टा जिसके लिए, छावनी बोर्ड अधिनियम की धारा 123 के अधीन स्वयं उपयोजन नहीं कर सकता था, संपत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी;
- (iv) प्रत्येक पट्टे पर, वे शर्तें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जिस प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति का पट्टेदार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा और उसमें छावनी बोर्ड को इस बात के लिए शक्ति प्रदान करने वाला खंड होगा कि छावनी बोर्ड की सम्मति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए संपत्ति का उपयोग किए जाने की दशा में वह पट्टे को निराकृत कर दे;
- (v) छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, खंड (iv) के अनुसरण में इसकी सम्मति नहीं देगी यदि ऐसी सम्मति, पट्टे पर दी गई संपत्ति के ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए चाही गई है जिसके लिए स्वयं छावनी बोर्ड भी इस अधिनियम की धारा 123 के अधीन संपत्ति का उपयोजन नहीं करता;
- (vi) जहां पट्टेदार, पट्टे की निबंधन के उल्लंघन में और छावनी बोर्ड की सम्मति के बिना पट्टे पर दी गई संपत्ति का किसी प्रयोजन के लिए ऐसा उपयोग करता है जिसके लिए स्वयं छावनी बोर्ड भी अधिनियम की धारा 123 के अधीन उस संपत्ति का उपयोजन नहीं कर सकता तो छावनी बोर्ड ऐसे पट्टे को तुरंत निराकृत कर देगा, ऐसी संपत्ति का नया पट्टा केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित ऐसी शर्तों पर प्रदान किया जाएगा:

परन्तु अधिनियम की धारा 257 के उपबंधों के अधीन, ऐसी स्थावर संपत्ति जो पथ है या जिसमें किसी पथ का भाग सम्मिलित है, पट्टे पर नहीं दी जाएगी।

9. केन्द्रीय सरकार को स्थावर संपत्ति अंतरण करने की शक्ति - इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, छावनी बोर्ड किसी स्थावर संपत्ति को जो इस अधिनियम की धारा 122 के अधीन उसमें निहित है और उसकी है, केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर सकेगा किन्तु इस प्रकार नहीं कि किसी न्यास या लोक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिसके अधीन वह संपत्ति धारित है।

10. स्थावर संपत्ति अर्जित व अंतरित करने की शक्ति.—इस अधिनियम की धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए छावनी बोर्ड, किसी ऐसी जंगम संपत्ति को अर्जित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और किसी ऐसी जंगम संपत्ति को जो छावनी बोर्ड में निहित है या उसकी है, किसी रीति में या किन्हीं ऐसे निबंधनों पर अंतरित कर सकेगा जो साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा समीचीन और युक्तिसंगत अवधारित करें।

11. रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा प्रवेश, निरीक्षण-

- (1) रक्षा सम्पदा अधिकारी या साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सहायकों या कर्मचारों के साथ या उनके बिना अधिनियम की धारा 122 के अधीन छावनी बोर्ड में निहित किसी भवन में या भूमि पर कोई ऐसी जांच, निरीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो ऐसे अधिकारी या व्यक्ति आवश्यक समझे या किसी ऐसे संकर्म के परीक्षण या निरीक्षण के लिए आवश्यक समझे जो ऐसे भवन या भूमि पर निष्पादित हुआ है या होता रहा है या जिसे निष्पादित किया जाना है।

- (2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में, ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो अधिनियम के अध्याय xv में प्रवेश और निरीक्षण प्रयोजनों के लिए अभिकथित हैं।

[फा. सं. 14(4)/2009-डी (क्यू एवं सी)]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2017

S.R.O. 5(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 125 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), and in supersession of the Cantonment Property Rules, 1925 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director (L and C), Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi- 110001.

1. **Short title extend and commencement.**—(1) These rules may be called the Cantonment Property Rules, 2017.
(2) These rules shall extend to all cantonments in India.
(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise require,
(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
(b) "immovable property" includes land, benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to things attached to the earth but does not include standing timber, growing crops or grass;
(c) "movable property" includes standing timber, growing crops and grass, fruit upon and juices in trees, bark, lac and property of every other description except immovable property;
3. **Register of cantonment property.**—Registers of immovable property, which vest in and belong to the Cantonment Board, shall be maintained by the Cantonment Board in the forms prescribed by relevant rules of the Account Code and all additions to or alterations in the holdings of the Cantonment Board shall be recorded therein.
4. **Purchase or lease of land other than land vested in the Central Government.**—Subject to the provisions of section 123 and section 124 of the Act, the Cantonment Board may purchase or take on lease any immovable property, other than property which is vested in the Central Government that may be required for immediate and definite purpose connected with the administration of the cantonment:

Provided that the Cantonment Board shall not acquire any interest in any such property within the limits of the cantonment except with the sanction of the General Officer Commanding-in-Chief, the Command, who shall obtain comments of the Principal Director, Defence Estates before according or refusing sanction.
5. **Application for acquisition of land under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.**— In making an application to the Central Government under section 124 of the **Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)** for the acquisition of land, the Cantonment Board shall state clearly the necessity for the acquisition and shall submit an estimate of the compensation to be paid and any revenue to be remitted and the Cantonment Board shall also certify that acquisition by private contact has been found impracticable or is, for special reasons, undesirable.
6. **Transfer of land vested in the Central Government to Cantonment Board.**—When any land in the cantonment, which is vested in the Central Government, is required by the Cantonment Board for a purpose

connected with the administration of the cantonment, the Cantonment Board may apply to the Central Government for the grant of the land stating the reasons and purpose **for** which it shall be **utilised** and if the Central Government considers that the application shall be accepted, they may transfer the land to the Cantonment Board on such conditions, if any, as they may think fit:

Provided that –

- (a) if the land applied for is already occupied for any other purpose, its transfer to the Cantonment Board shall be governed by the provisions of rule 7 of the Cantonment Land Administration Rules, 1937 or by the relevant rule of the Cantonment Land Administration Rules in force; or
- (b) if the land is required for an object from which the Cantonment Board will derive income of any description, it may be transferred to the Cantonment Board only on such payment made in such manner as the Central Government may consider equitable in each case;
- (c) if at any time the land is not used for the object for which it was granted to the Cantonment Board, or if there has been, in the opinion of the Central Government, any other breach of the conditions on which it was transferred to the Cantonment Board, or if the land is required for a general public purpose, the Central Government may, after giving opportunity to the Cantonment Board to show cause and considering the cause shown, resume possession of the land and for any land so resumed by the Central Government the amount of compensation payable to the Cantonment Board shall be decided by the Central Government in each case and shall in no circumstances exceed the amount, if any, paid to the Central Government by the Cantonment Board for the transfer of the land together with the initial cost or the present value, whichever is less, of buildings, if any, erected thereupon.

7. **Transfer by Cantonment Board of Immovable Property.-** Immovable property which vests in and belongs to the Cantonment Board shall not be transferred to any person by the Cantonment Board by way of sale, mortgage or exchange, or otherwise than by lease without a premium, except with the previous sanction of the Central Government and in such manner and on such terms and conditions as the Central Government may, approve such sanction:

Provided that if the immovable property is situated beyond the limits of the Cantonment, the views of the State Government and the services shall be ascertained by the Cantonment Board and communicated to the Central Government through the Principal Director, Defence Estates, the Command, shall be taken into consideration by the Central Government.

8. **Lease by Cantonment Board.-** Subject to the provisions of section 267 of the Act, immovable property which vests in and belongs to the Cantonment Board may be leased by the Cantonment Board without a premium on the following conditions, namely:-

- (i) that a reasonable rent is reserved and made payable during the whole term of the lease or, in the alternative, a suitable revenue generating model duly approved by the Principal Director is devised;
- (ii) that the lease, or the agreement for the lease, is not made for any term without the previous sanction of the Cantonment Board by resolution at a general meeting; or for any term exceeding five and not exceeding twenty years without the sanction of the Principal Director; or for any term exceeding twenty and not exceeding thirty years without the sanction of the General Officer Command-in-Chief, the Command; or for any term exceeding thirty years without the sanction of the Central Government.
- (iii) that a lease for any purpose **for** which the Cantonment Board itself could not, **utilize** the property, under section 123 of the Act, shall require the previous sanction of the Central Government;
- (iv) that every lease shall specify in clear terms the purpose or purposes to which leased property may be put by the lessee, and shall contain a clause empowering the Cantonment Board to abrogate the lease in the event of the property being used for any other purpose without the consent of the Cantonment Board;
- (v) that the Cantonment Board shall not give its consent in pursuance of clause (iv) without the previous sanction of the Central Government if such consent is sought for use of the leased property for a purpose **for** which the Cantonment Board could not itself apply the property under section 123 of the Act;
- (vi) that where the lessee, in contravention of the terms of the lease and without the consent of the Cantonment Board, uses the leased property for any purpose to which the Cantonment Board could not itself **utilize** the property under section 123 of the Act, the Cantonment Board shall forthwith abrogate the lease, **and any fresh lease of the same property to the lessee shall be granted** only

with the previous sanction of the Central Government and on such terms as the Central Government may direct:

Provided that subject to the provisions of section 257 of the Act, any immovable property which is, or includes a part of a street shall not be given **on** lease.

9. **Power to transfer immovable property to the Central Government.**—Notwithstanding anything contained in these rules, the Cantonment Board may transfer to the Central Government any immovable property which vests in and belongs to it under section 122 of the Act, but not so as to affect any trusts or public rights subject to which the property is held.
10. **Power to acquire and transfer movable property.**—Subject to the provisions of section 123 of the Act, the Cantonment Board may acquire any movable property that may be required for the purposes of the Act, and may transfer any movable property which vests in and belongs to the Cantonment Board in any way and on any terms that it may, by resolution at a general meeting, determine to be expedient and reasonable.
11. **Entry, inspection by Defense Estates Officer.**—
- (1) The Defence Estates Officer, or any person authorised by him by general or special order may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any building or land vesting in Cantonment Board under section 122 of the Act, for the purpose of making any enquiry, inspection, measurement, valuation or survey, which such officer or person may consider necessary, or **for** examining or inspecting any works which have been, are being, or are to be executed in or on such building or land.
 - (2) In the performance of the duties specified in sub-section (1), such officer or person shall observe the same procedure for the purposes of entry and inspection as is laid down in Chapter XV of the Act.

[F. No. 14(4)/2009-D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.